www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 284 | जौनपुर शुक्रवार, 05 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर योगी सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद, (एजेंसी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान ग्राम प्रधानों (ग्राम प्रमुखों) का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाया है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तारीख निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया है। यह टिप्पणी बुधवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के 25 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें ग्राम प्रधानों को अगले पंचायत चुनावों तक अपने प्रशासनिक पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी सहित दो न्यायाधीशों की बेंच ने राज्य सरकार को पंचायत चुनावों से संबंधित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 25 मई के अपने आदेश में 57,694 ग्राम प्रधानों को नए पंचायत निकायों के गठन तक अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी है। मौजूदा निकायों का कार्यकाल इस वर्ष 26 मई को समाप्त होना था, लेकिन पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत इसे बढ़ा दिया था।

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भीषण आग से 4 की मौत

मुजफ्फरपुर, (संवाददाता)। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग से हड़कंप मच गया। इस दाहसे में 4 लोगों की जान चली गई। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कई मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पोक्ट में लिखा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है। शोक–संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें।सीएम सम्राट ने मृतकों के परिजनों को अविलंब 4–4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार हेतु सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आईएएनएस से बताया कि आईसीयू में आग लगने से भारी मात्रा में धुआं फैल गया। मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। लोगों के अनुसार, यूनिट के इंचार्ज को भी अन्य मरीजों के साथ गंभीर चोटें आई हैं। अब तक तीन लोगों की मौत की खबर है। आईसीयू और सीसीयू में भर्ती अन्य मरीजों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है।

पीएम मोदी ने 21,700 करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेन्द्र मोदी कल (5 जून) गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो गुजरात के सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपये और दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए 885 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज बताया कि वो कल दोपहर करीब 2:30 बजे सूरत जिले के हजीरा पहुंचकर वहां चल रही औद्योगिक गतिविधियों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री वडोदरा–मुंबई आठ लेन नियंत्रित प्रवेश (एक्सेस कंट्रोल्ड) एक्सप्रेसवे के पैकेज–6 और पैकेज–7 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही वह राष्ट्रीय राजमार्ग–56 के महत्वपूर्ण हिस्सों को चार लेन बनाने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे आदिवासी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच आसान बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के साथ केंद्रीय प्रयोगशाला तथा 24 घंटे आपात और ट्रॉमा देखभाल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा वह अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली के तहत गुजरात की ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वलसाड में विद्युत वितरण प्रणाली उन्नयन, दहेज पेट्रोलियम–रसायन एवं पेट्रो–रसायन निवेश क्षेत्र तथा सरीगाम औद्योगिक विकास निगम में अपशिष्ट निस्तारण एवं शोधन अवसंरचना और जंबूसर बल्क ड्रग पार्क की उपयोगिता परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

सरकार 2027 तक 5,000 ई85 ईंधन स्टेशन शुरू करेगी` हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत देश में फ्लेक्स–फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से म85 ईंधन वितरण स्टेशनों का विस्तार करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , मुंबई, पुणे और नागपुर सहित प्रमुख शहरी गलियारों में शुरुआत में 100 तक म85 ईंधन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल के लॉन्च कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि म85, जिसमें 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित होता है, को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के तहत फ्लेक्स–फ्यूल वाहनों के लिए मोनो–फ्यूल मानक के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि ई85 को भारत के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ते कदम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में भी सबसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों में से एक माना जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि फ्लेक्स–फ्यूल अवसंरचना का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। दिसंबर 2026 तक ई85 स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी और 2027 के अंत तक देश के प्रमुख शहरों में 5,000 आउटलेट स्थापित करने का लक्ष्य है। भारत की परिवहन व्यवस्था में हो रहे बदलाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि फ्लेक्स–फ्यूल तकनीक अब दोपहिया वाहनों से आगे बढ़कर चारपहिया वाहनों तक पहुंच चुकी है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उत्तर पूर्वी परिषद के 73वां पूर्ण सत्र का गुरुवार को शिलांग में आयोजन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) का 73 वां पूर्ण सत्र 4 जून, 2026 को मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री और एनईसी के अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत गठित उत्तर पूर्वी परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है और इस क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्र में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री और एनईसी के उपाध्यक्ष ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, डीओएनईआर राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, परिषद के अन्य सदस्य और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कल गुरुवार को होने वाले पूर्ण सत्र में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्य बलों की प्रगति पर चर्चा और विचार–विमर्श किया जाएगा। सत्र में पर्यटन, कृषि एवं बागवानी, निवेश प्रोत्साहन, दूध, अंडे, मांस और मछली उत्प्पादन में आत्मनिर्भरता, खेल प्रोत्साहन, आर्थिक गलियारे के विकास, अवसंरचना एवं संपर्क और हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर प्रस्तुतियां भी शामिल हैं।

रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाएं : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रतिनिधि प्रदेश है। पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुरुवार को पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खानपान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम् मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण और डिजिटलीकरण केवल अभिलेखीकरण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। बैठक में अब तक 13 लाख 70 हजार से अधिक पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण और संरक्षण की प्रगति की जानकारी दी गई। पर्यटन नीति–2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। बैठक में नीम करोली बाबा सर्किट तथा बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के रूप में नए क्षेत्रों के विकास पर चर्चा हुई। साथ ही 'परंपरा' विरासत अनुभव केंद्र, कृषि पर्यटन तथा वाइनयार्ड पर्यटन जैसी नई अवधारणाओं को बढ़ावा देने पर भी विचार–विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नीति ऐसी हो जो निवेश आकर्षित करे, रोजगार बढ़ाए और पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करे।

संवैधानिक संस्थाओं पर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज, बढ़ीं मुश्किलें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह ने 4 जून को सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बनर्जी ने संवैधानिक संस्थानों और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और मानहानिकारक बयान दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में, विभिन्न सार्वजनिक भाषणों, राजनीतिक मंचों और मीडिया से बातचीत के माध्यम से, आरोपी ने कथित तौर पर भारत के संवैधानिक संस्थानों, जिनमें भारतीय चुनाव आयोग और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल शामिल हैं, के खिलाफ कई भड़काऊ और उत्तेजक बयान दिए हैं। आरोपी ने सार्वजनिक रूप से इन संवैधानिक संस्थानों की निष्ठा, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिससे कथित तौर पर राज्य तंत्र के खिलाफ जनता में अविश्वास और असंतोष पैदा करने का प्रयास किया गया। इस बारे में बात करते हुए रिंकी चटर्जी सिंह ने कहा कि मेरी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत है। इस शिकायत को औपचारिक रूप से एफआईआर में बदलने में 23 दिन लगेंगे... महीने की 2 तारीख को एक जनसभा में उन्होंने चुनाव आयोग को निशाना बनाना शुरू किया। बाद में उन्होंने केंद्रीय बलों की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अचानक बांग्लादेश में हादी (बांग्लादेशी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान बिन हादी) की राजनीतिक हत्या का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या बांग्लादेश में नहीं हुई। यह मणिपुर में हुई, जहां एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था... उन्हें इन तथ्यों की पूरी जानकारी थीय उस समय उन्हें इस मामले के संबंध में एक फोन कॉल भी आया था। फिर भी उन्होंने पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला, इन सभी कार्यों सहित, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा परिभाषित राज्य के विरुद्ध अपराधों के दायरे में आता है। इसमें राजद्रोह, आपराधिक उकसावा और आधिकारिक गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है।

ब्लू इकोनॉमी के दम पर वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा भारत : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत की ब्लू इकोनॉमी (समुद्री अर्थव्यवस्था) तेजी से विकास का एक शक्तिशाली इंजन बनकर उभर रही है। इसकी प्रमुख वजह समुद्री खाद्य उत्पादों (सीफूड) के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी और वैश्विक बाजार में भारतीय समुद्री उत्पादों की बढ़ती मांग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के मछुआरों को अब बड़े बाजारों तक पहुंच और बढ़ते निर्यात अवसरों का लाभ मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2013–14 की तुलना में समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, "हमारे मछुआरों को नए बाजारों और बढ़ते निर्यात का लाभ मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025–26 में समुद्री खाद्य निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2013–14 से निर्यात में लगभग 145 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत की ब्लू इकोनॉमी विकास के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही है।" इस बीच, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह उपलब्धि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं के बावजूद इस क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाती है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत ने 19.72 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 73,890 करोड़ रुपए (8.46 अरब डॉलर) रही।

आर्थिक स्थिति पर सरकार घबराहट में, अध्यादेश सिर्फ दिखावा : जयराम रमेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 जून को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मोदी सरकार पर मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण घबराहट की स्थिति में होने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि मोदी सरकार स्पष्ट रूप से घबराहट की स्थिति में है और मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर अपने ही तंत्र के भीतर से ही घिरी हुई है। उन्होंने टेलीविजन पर प्रसारित एक समाचार का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 12.5% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि सत्ताधारी दल से जुड़े एक टीवी चौनल के समाचार के अनुसार, मोदी सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 12.5% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यह दर जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में निर्धारित की गई थी। उन्होंने प्रस्तावित उपाय को एक अस्थायी समाधान बताया जो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करने में विफल है।

मौसम की मार, फिर भी राहुल गांधी का परिवर्तन का शंखनाद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा की अपनी निर्धारित यात्रा स्थगित करनी पड़ी और खराब मौसम की स्थिति में हेलीकॉप्टर के फंस जाने के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही पंतनगर हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बाद में कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी सेल्जा द्वारा सुगम बनाए गए फोन कॉल के माध्यम से परिवर्तन का शंखनाद शीर्षक से एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं, एक्स पर राहुल ने एक वीडियो साक्षा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे मिलना चाहता था, आपके बीच बैठकर आपकी बातें सुनना चाहता था, आपके सुख–दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से, मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैं पंतनगर पहुँच गया था। वहाँ से हमें हेलिकॉप्टर द्वारा अल्मोड़ा में जनसभा के लिए जाना था, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए पायलट ने उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी थीं – उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, राज्य और आपके भविष्य पर, और उन चुनौतियों पर जिनका सामना आज उत्तराखंड कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक निर्धारित थी। साथ ही कोटद्वार में दीपक के जिम जाने का भी कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि प्रकृति के आगे हम सभी विनम्र हैं और सहयात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कई बार परिस्थितियाँ हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होतीं, लेकिन इससे मिलने की इच्छा और आपसे जुड़ाव कम नहीं होता। राहुल ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द फिर उत्तराखंड आऊँगा। तब हम जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरा समय निकालकर मिलेंगे, बात करेंगे, आपके विचार सुनेंगे और मिलकर प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा में चर्चा करेंगे। जल्द ही मुलाकात होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ।

संपादकीय

आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में पहली कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर भाजपा से जवाब मांगा है। कांग्रेस और वामदलों ने नरेन्द्र मोदी के भाषण को विभाजनकारी और महाहानिकर बताते हुए आयोग से शिकायत की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरुद्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है। उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इम्तिहान दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा–मर्यादा और नियम–कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा–सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या–क्या न कहा गया। माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय–धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष–रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया। विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने–देखे गए हैं, बल्कि तू–तड़ाक पर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।

ताकि अलनीनो का कम पड़े दुष्प्रभाव

उमेश

वर्षा की कमी के कारण भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज कम होता है, जिससे भूजल स्तर और नीचे चला जाता है। वैसे भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में पहले से ही भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसलिए सूखे की स्थिति विशेषकर उत्तर–पश्चिम और मध्य भारत के लिए बहुत खतरनाक है। साल 2026 में प्रशांत महासागर में सक्रिय श्अल नीनोश का साया भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार, इस वर्ष मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका जताई है। नए पूर्वानुमान के अनुसार, इस साल औसत से करीब दस फीसद कम बारिश होने की आशंका है। भारत में, जहाँ कृषि अभी– भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, उसके लिए मानसूनी बारिश की कमी और भीषण सूखा एक तरह से विपत्ति का ही द्योतक है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सिंचाई का भी प्रबंधन किया जाए। भारत की करीब साठ प्रतिशत अब भी सीधे तौर पर खेती–किसानी पर निर्भर है। सूखे की मार की वजह से इस बड़ी आबादी के सामने सहज तरीके से रोजी–रोटी का संकट उठ खड़ा होगा। इससे बचाव के लिए जरूरी होगा कि सिंचाई के ऐसे साधनों और तकनीक को अपनाया जाए, जिनके जरिए पानी को बचाया जा सके और तुलनात्मक रूप से ज्यादा पैदावार ली जा सके। अल नीनो का दूसरा अर्थ है, कम वर्षा और भीषण सूखा। इस परिस्थिति में भारत में सिंचाई साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनसे न केवल फसलों का बचाव हो सके, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। जहाँ तक भारत में सिंचाई व्यवस्था की बात है, तो मुख्य रूप से यह भूजल और सतही जल यानी नहरों और तालाबों पर आधारित है। चूँकि इस साल अल नीनो के कारण कम बारिश होने की आशंका है, इसलिए इन साधनों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। वर्षा की कमी के कारण भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज कम होता है, जिससे भूजल स्तर और नीचे चला जाता है। वैसे भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में पहले से ही भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसलिए सूखे की स्थिति विशेषकर उत्तर–पश्चिम और मध्य भारत के लिए बहुत खतरनाक है। अल नीनो के चलते इस साल वर्षों पहले बने बांधों और जलाशयों में पानी का भंडारण सामान्य से कम होने की आशंका है। इस पानी का इस्तेमाल ज्यादातर रबी फसलों के लिए होता है। जब पानी कम होगा तो रबी फसलों की सिंचाई के लिए कम उपलब्ध होगा। अल नीनो के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों के सूखे की चपेट में आना स्वाभाविक है। इसकी वजह से पैदावार पर बुरा असर पड़ना तय है। इससे फसलों की बुवाई में देरी हो सकती है और फसलों की बुआई के लिए अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भूजल की आवश्यकता होगी और उसे चूँकि ट्यूबवेल से निकाला जाएगा, लिहाजा बिजली की माँग बढ़ेगी। इसके लिए सिंचाई के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि किसानों को कम पानी की जरूरत वाली फसलों, जैसे बाजरा, मूँग, अरहर, मक्का आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपाय को अपनाने की बात भी की है। सरकार की ओर से इस संबंध में किसानों को तैयार भी किया जा रहा है। इसके तहत मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए पौधों की जड़ों के आसपास सूखी पत्तियों या प्लास्टिक की शीट की परत बिछाने का सुझाव दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, देशी पौधों को आमतौर पर बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है या वे अन्य प्रकार की घासों, पेड़ों और झाड़ियों की तुलना में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान और बागवानी करने वाले लोग अपने बगीचों या यहां तक कि अपने व्यवसायों के सामने भी पत्थरों या अन्य प्रकार के भू–आवरण का उपयोग करके रचनात्मक तरीके से पानी को बचा सकते हैं । कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार शुष्क बागवानी के मूल सिद्धांत हैं कि पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग किया जाए और ऐसी बागवानी डिजाइन और पौधों का चयन किया जाए जो उपलब्ध वर्षा जल का उपयोग कर सकें। इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था को भी अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे पानी की खपत को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही खेत के तालाबों और जल संचयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो सूखे की हालत में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। किसानों को जरूरत के हिसाब से खेत के उन क्षेत्रों में सिंचाई किया जाना होगा, जिसे पानी की जरूरत ज्यादा हो।

ममता बनर्जी की राजनीति खत्म या पिक्चर अभी बाकी है

नीरज

पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ सप्ताहों के भीतर जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसने तृणमूल कांग्रेस और उसकी संस्थापक ममता बनर्जी

के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद पार्टी के भीतर लंबे समय से सुलग रहा असंतोष अब खुली बगावत में बदल चुका है। महज 13 दिनों के भीतर घटनाओं की ऐसी श्रृंखला सामने आई, जिसने 28 वर्ष पुरानी पार्टी को विभाजन की कगार पर पहुंचा दिया। हम आपको याद दिला दें कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर की थी। इसके बाद उन्होंने वाम मोर्चे के लंबे शासन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया और 2011 में ऐतिहासिक जीत हासिल कर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया। 2016 और 2021 के चुनावों में भी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली हार ने पार्टी की राजनीतिक जमीन हिला दी। सबसे बड़ा झटका यह था कि ममता बनर्जी को अपने पारंपरिक गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही विधानसभा में टीएमसी की संख्या घटकर केवल 80 विधायकों तक सिमट गई। चुनावी हार के बाद ही पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ने लगा था। कई विधायकों को लगने लगा कि संगठन और निर्णय प्रक्रिया में सांसद अभिषेक बनर्जी का प्रभाव लगातार बढ रहा है। पार्टी के भीतर यह धारणा मजबूत होने लगी कि तृणमूल का केंद्र धीरे–धीरे एक परिवार तक सीमित होता जा रहा है। छह मई को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी द्वारा अभिषेक बनर्जी के लिए खड़े होकर तालियां बजाने का आग्रह इस असंतोष को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। पार्टी में मतभेद पहली बार खुलकर 19 मई को सामने आए, जब रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि चुनाव से हटने की घोषणा करने वाले विधायक जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चूंकि जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, इसलिए इसे सीधे तौर पर अभिषेक के प्रभाव को चुनौती माना गया। इसके बाद घटनाओं ने तेजी पकड़ ली। 22 मई को दिल्ली के बंग भवन में रिताब्रता बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कथित मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। रिताब्रता ने बाद में विपक्षी नेताओं को प्रशासनिक बैठकों में बुलाने के शुभेंदु अधिकारी के फैसले की सार्वजनिक सराहना की। इसके बाद तृणमूल के भीतर संदेह और गहरा गया। 25 मई को विवाद ने नया मोड़ लिया, जब विधायक दल के नेतृत्व से जुड़े दस्तावेजों पर जाली हस्ताक्षर किए जाने के आरोप सामने आए। रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी औपचारिक शिकायत की। मामला पुलिस और सीआईडी जांच तक पहुंच गया। इसके साथ ही पार्टी के भीतर का असंतोष खुली राजनीतिक लड़ाई में बदल गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 30 मई को अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला हुआ। हालांकि सभी दलों ने इसकी निंदा की, लेकिन तृणमूल के भीतर अपेक्षित एकजुटता दिखाई नहीं दी। इससे साफ संकेत मिला कि नेतृत्व और विधायकों के एक हिस्से के बीच दूरी बढ़ चुकी है। 31 मई को ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट आवास पर बैठक बुलाई, लेकिन उसमें कम उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। आखिरकार एक जून को पार्टी ने रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया। लेकिन यह कदम बगावत रोकने की बजाय उसे और तेज करने वाला साबित हुआ। बागी खेमे ने अपनी मुहिम को "ऑपरेशन क्राउन प्रिंस" नाम दिया, जिसे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अभियान के रूप में देखा गया। बुधवार को यह संकट निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर रिताब्रता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुनने की जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दावे को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही बागी गुट को तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक विधायक दल के रूप में मान्यता मिल गई। यह ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका स्पष्ट वैचारिक आधार न होना रहा है। वाम विरोधी की राजनीति ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद संगठनात्मक एकता कमजोर पड़ती गई। अब जब चुनावी हार ने पार्टी की शक्ति कम कर दी है, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और उत्तराधिकार की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। फिर भी ममता बनर्जी को राजनीति से बाहर मान लेना जल्दबाजी होगी। बंगाल की राजनीति में उनका संघर्ष, जनाधार और राजनीतिक अनुभव अभी भी उन्हें एक मजबूत नेता बनाता है। लेकिन यह भी सच है कि तृणमूल कांग्रेस अब अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है और आने वाले समय में यह तय होगा कि पार्टी इस संकट से उबर पाएगी या बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

बंगाल में भाजपा का महाराष्ट्र मॉडल

मोहन

पश्चिम बंगाल की सियासत में घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जब बिसात पलट दी और ममता बनर्जी को हरा कर भाजपा पहली बार सत्ता में आई, तो उसके बाद कायदे से नयी सरकार की प्राथमिकताओं और घोषणापत्र पर अमल की शुरुआत पर चर्चा होनी चाहिए थी। भाजपा ने बार–बार बंगाल में सकारात्मक बदलाव लाने का दावा किया था, तो वह दावा सतह पर दिखना भी चाहिए थे। लेकिन इसकी जगह कभी राजनैतिक विरोधियों के साथ हिंसा, कभी मुसलमानों के लिए फरमान, कभी बुलडोजर कार्रवाई की खबरें आईं या फिर तृणमूल कांग्रेस किस तरह विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसकी खबरें आईं। इस बीच अब एक और ऐसा घटनाक्रम चल रहा है, जो नया नहीं है, लेकिन चौंकाता जरूरी है कि आखिर कब तक सत्ता पर बने रहने के लिए यही दांव–पेंच एक राज्य से दूसरे राज्य में खेले जाते रहेंगे।दरअसल प.बंगाल में अब तक भाजपा बनाम टीएमसी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब टीएमसी बनाम टीएमसी की लड़ाई छिड़ गई है। महज 80 सीटों पर सिमटने वाली टीएमसी अब दो फाड़ होने की कगार पर आ गई है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष रथीन बोस को टीएमसी के 58 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतब्रत बंद्योपाध्याय के नाम का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष ने इस पत्र को स्वीकार कर लिया है।पाठक जानते हैं कि प.बंगाल विधानसभा में बीते दिनों जाली हस्ताक्षर कांड के आरोप टीएमसी पर लगे, जिसकी अब सीआईडी जांच हो रही है। खुद मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी ने बताया था कि टीएमसी के दो विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने शिकायत की थी कि विधानसभा में पार्टी विधायक दल का नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को चुनने के लिए जो बैठक हुई थी उसमें पारित प्रस्ताव पर कथित तौर पर उन विधायकों के भी हस्ताक्षर थे जो उस बैठक में हाजिर ही नहीं थे। मुख्यमंत्री के इस बयान के 15 मिनट बाद ही दोनों विधायकों को पार्टी से बाहर करने का फैसला सुना दिया गया था। इसके एक दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रिजू दत्त ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया था कि उन लोगों के पास 50 विधायकों का समर्थन है और वही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। बगावत की चिंगारी शांत करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने घर पर बैठक बुलाई तो उसमें केवल 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद बैठक रद्द करनी पड़ी। अभी मंगलवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में राशोमनी एवेन्यू पर जो धरना–प्रदर्शन किया, उसमें भी भीड़ तो बहुत जुटी, लेकिन पार्टी के विधायक नदारद रहे, हालांकि अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी जैसे कुछ दिग्गज पहुंचे हुए थे। ये सारा घटनाक्रम बता रहा है कि अब टीएमसी एकजुट नहीं है। टीएमसी के भीतर बगावत के सुर इतने तेज हो गए हैं कि सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी भी उसी रास्ते पर जा रही है, जिस पर कभी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी गई थीं।गौरतलब है कि 1970 के दशक तक बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर राय के बीच की खींचतान और बाद में कांग्रेसी नेताओं का बार–बार टूटकर तृणमूल या वाम दलों में जाना, पार्टी को हाशिए पर ले गया। फिर 2011 में 34 साल बाद सत्ता से बाहर हुए वाम मोर्चे से बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता टूटकर टीएमसी में चले गए। खुद ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और अपनी आक्रामक छवि के सहारे सत्ता तक पहुंची थीं। अब टीएमसी में फूट बंगाल के इतिहास को दोहराते हुए ही नजर आ रही है।प्रत्यक्ष तौर पर तो टीएमसी का सत्ता से बाहर होना ही इस टूट का प्रमुख कारण दिख रहा है। लेकिन जानकार इसे भाजपा का महाराष्ट्र मॉडल पर चलना बता रहे हैं। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के बूते कई विधायकों को साथ लेकर भाजपा ने नयी शिवसेना बनवाई और बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान भी शिंदे के ही सुपुर्द किया। उद्धव ठाकरे की सरकार एकनाथ शिंदे को साथ लेकर जिस तरह भाजपा ने गिराई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना था, लेकिन फिर भी शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और भाजपा सरकार का हिस्सा बनी रही। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को साथ भी यही काम भाजपा ने किया। अजित पवार ने अलग एनसीपी बना ली और शरद पवार को ही बाहर किया गया। एनसीपी का नाम और निशान अजित पवार गुट को ही मिला। बिल्कुल इसी तर्ज पर अब टीएमसी और न्यू टीएमसी दो दल बनाए जा सकते हैं। देखना यही होगा कि क्या ममता बनर्जी के खाते में नाम और निशान आते हैं या नहीं।इस खेल में प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा नहीं दिख रही है, लेकिन यह महज संयोग नहीं है कि उसके सत्ता में आते ही विपक्षी दल में फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बागी विधायक डर के मारे सीधे तौर पर भाजपा के सामने झुक रहे हैं। आज टीएमसी के जो चुने हुए प्रतिनिधि

एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्योंकि भाजपा के पास पहले से ही ईडी और सीबीआई थीं। अब सीआईडी और बंगाल पुलिस भी उनके साथ हो गई हैं। टीएमसी के ये विधायक बस खुद को बचाना चाहते हैं। इन विधायकों को खुद को बचाने का एक रास्ता मिल जाएगा और भाजपा को सदन में बिना किसी रुकावट के कुछ भी करने की पूरी आजादी मिल जाएगी। अधीर रंजन चौधरी की तरह ही कई और जानकारों का मानना है कि भाजपा दबाव के लिए जांच एजेंसियों को आगे करती है और विरोधी दलों में ऐसे ही फूट पड़वाती है। हालांकि टीएमसी तोड़ने वाले विधायक भाजपा में सीधे तौर पर शामिल न होकर नयी पार्टी बना रहे हैं, तो उसके पीछे किसी एक का विकल्प रहेगा। वैसे टीएमसी में टूट के फिलहाल दो बड़े असर दिखाई दे सकते हैं, पहला बंगाल में कमजोर विपक्ष के कारण भाजपा को मनमाने फैसलों की छूट मिलेगी, दूसरा, आठ जून को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने विपक्ष को मजबूत कर भाजपा को खत्म करने की चुनौती दी थी। ममता अब भी यही कह रही हैं कि भाजपा को हराए बिना वो मरेंगी नहीं।

तालमेल और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता

प्रो. लल्लन प्रसाद

गेहूं और सरसों की फैसल तैयार है, मंडियों में खरीदारी शुरू हो गई है। कुछ मंडियों में सुचारू रूप से खरीदारी हो रही है किंतु ऐसी बहुत सी मंडियां हैं, जहां किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कहीं बारिश और ओले के कारण खेत में अनाज गीला हो गया है तो कहीं मंडी में खुले आसमान के नीचे। किसान की गाढ़ी कमाई पर पानी फिर रहा है, अधिकारी नम माल लेने से मना कर रहे हैं। मंडियों में अव्यवस्था के कारण किसान का सब्र टूट रहा है और कुछ जगहों पर किसानों ने अपना रोष भी प्रकट किया है। अनेक मंडियों में उठान की स्थिति खराब है, शेड में, बाहर सड़क पर माल पड़ा है, टोकन काटने की व्यवस्था ठीक नहीं है। कभी–कभी मंडी के आगे मीलों लंबी लाइन लग जाती है, रात रात भर किसान को जागकर अपने माल की सुरक्षा करनी पड़ती है। मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का स्वच्छ पानी, शौचालय और साफ–सफाई का अभाव है। मंडी को जाने वाली सड़कों में गड्ढे, अवैध रूप से खड़े वाहन और आवारा पशु, जगह–जगह जाम की समस्या से किसानों को जूझना पड़ता है। कुछ मंडियों में कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ की कमी है तो कुछ में तौल के लिए कांटे की व्यवस्था भी समय पर नहीं हो पाई। आवश्यक मात्रा में बारदानों (कट्टों) का अभाव भी परेशानी का कारण बन जाता है। यद्यपि सभी मंडियों में ऐसी अव्यवस्था नहीं है किंतु काफी संख्या में ऐसे मंडी है जहां व्यवस्था सुधार की एवं मंडी प्रबंधकों और सरकारी विभाग के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। अनाज की खरीद के सीजन में मंडियों से जो रिपोर्ट आ रही हैं वे चिंताजनक हैं। चरखी दादरी में पहले ही दिन मंडी में हजारों किसान फसल लेकर पहुंचे, लंबी लाइन लग गई, किसानों के वाहन घंटों जाम में फंसे रहे, पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। बैकडोर से टोकन लेने और व्यापारियों के वाहनों को बैकडोर से एंट्री देने के आरोप लगे। रोहतक की एक मंडी में किसानों को मजबूरी में अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को बेचने के आरोप लगे। ओला और बे मौसम बारिश की वजह से वहां फसल खराब हुई, अधिकारी फसल में नमी के कारण खरीद नहीं कर रहे थे। सोनीपत के गन्नौर में मंडी सेक्रेटरी और अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को जो नुकसान हुआ उससे उनमें जबरदस्त रोष था, मंडी पर उन्होंने ताला लगा दिया। पोर्टल पर फसल रजिस्ट्रेशन करवाने में भी धांधली के आरोप लगे। जहां किसान की 5 से 6 एकड़ का रजिस्ट्रेशन था वहां अधिकारी 1 से 2 एकड़ का माल ही खरीद रहे थे। भिवानी की एक मंडी में हजारों क्विंटल सरसों खरीद के बाद कट्टों में पड़ी बारिश में भीग गई, बचाव का कोई इंतजाम नहीं था। पूरी मंडी पानी से तरबतर थी, फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की आशंका से किसानों ने भारी मजदूरी देकर समय से फसल कटवा दिया था और अब जब फसल लेकर मंडी पहुंचे तो वहां मौसम की मार झेलनी पड़ी। सरसों का रंग भूरा हो गया और उसकी गुणवत्ता कम हो गई। सिरसा की मंडी में उठान की स्थिति बेहद खराब रिपोर्ट की गई। उठान के लिए एजेंसियों का चुनाव समय से नहीं हुआ। गेहूं की आवक एकाएक बढ़ जाने से अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे, टोकन काटने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं थे, ना ही पूरे कंप्यूटर ऑपरेटर। नियमानुसार फसल उठान ट्रकों द्वारा किया जाना चाहिए किंतु एजेंसी ट्रैक्टर–ट्राली द्वारा करा रही है जो सस्ती पड़ती है। यह तब हो रहा है जब ट्रैक्टर के कमर्शियल उपयोग पर रोक लगी हुई है। पंजाब की मंडियों में फसल पहुंच रही है, लेकिन खरीद का पुख्ता इंतजाम बहुत कम मंडियों में है। श्मेरी फसल मेरा ब्योराश्य के तहत प्रदेश के 9.25 लाख किसानों ने फसल बेचने के लिए 6.45 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया। आरोप लगाया जा रहा है कि 10. 40 एकड़ रकबा ऐसा है, जिसका डेटा मिसमैच कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई मंडियों में समय से उठान न होने से आवारा पशुओं से अनाज की रक्षा के लिए किसान रात रात भर जाकर अपने फसल की रक्षा करते हैं। अवैध रूप से ट्रक खड़े रहते हैं, मंडी को जोड़ने वाली सड़कों में गड्ढे, सफाई की कमी और मंडी में अतिक्रमण जैसी अव्यवस्था से किसान जूझ रहे हैं। देश के लगभग सभी प्रदेशों में मंडियों की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों दिल्ली की नरेला मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, उसमें करोड़ों रु पए का अनाज भीग गया था, बारिश से बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था।

मंडियों में व्यवस्था के खिलाफ आढ़तियों की अपनी शिकायतें हैं। उनका मानना है कि उन्हें जो आढ़त मिलती है वह कम हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं होते, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। मंडी के श्रमिकों के पारिश्रमिक के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए खाद्य पदाथरे और जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतें दिनों–दिन बढ़ रही है श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। किसानों को मंडी में अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिले इसके लिए आवश्यक है कि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दर पर खरीद ना की जाए। जहां अनाज में नमी उनकी गलती से ना हो उसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाए? मंडियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, खाने पीने की व्यवस्था और किसानों के रुकने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसानों तक पहुची यूद्रपीद्र एग्रीस परियोजना, विश्व बैंक मिशन ने प्रगति की सराहना की

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को अधिक उत्पादक, जलवायु–अनुकूल बाजारोन्मुख बनाने की दिशा में कार्यरत उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण परियोज (यू०पी०एग्रीस) ने अपने क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए अपने सभी चयनित जिलों में किसानों बीच कार्य आरंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाईड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपीडास्प) द्वारा संचाि एवं विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए विश्व का छह सदस्यीय सपोर्ट मिशन 1 से 5 जून तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा। मिशन के दौरान परियोजना की विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों का विस्तृत आक किया गया। समीक्षा में में यह सामने आया कि यूपीएग्रीज परियोजना अब राज्य के सभी 28 लक्षित जिलों में प्रभरूप से कार्य कर रही है और किसानों तक नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान, उन्नत तकनीकों तथा बेहतर बाजार अवसरों पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूपीएग्रीज का उद्देश्य कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और लाभकारी बनाना परियोजना के अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाली फसल प्रणालियों, जलवायु–स्मार्ट कृषि पद्धतियों, संसाधनों के कु उपयोग तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा

दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर धान उत्पादन क्षेत्र परियोजना अपने ज्ञान साझेदार इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्त्त्) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश विभिन्न जिलों में प्रदर्शन प्लॉट स्थापित कर रही है, जिनके माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता के व आदानों का निशुल्क वितरण भी किया जा रहा है। विश्व बैंक मिशन ने 1 जून को वाराणसी में धान उत्पादन में किए जा रहे नवाचारों का अवलोकन किया। इस दौ किसानों के साथ संवाद कर यह समझा गया कि नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादन क्षमता, लागत प्रबंधन खेती की जलवायु अनुकूलता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसानों ने परियोजना से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन प्रशिक्षण को लाभकारी बताया। इसी क्रम में 2 जून को मिशन ने बहराइच जिले के बघेल ताल क्षेत्र का दौरा कर कृषि सम्बद्ध क्षेत्र मत्स्यपालन अंतर्गत कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इनमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग एवं आनुवंशिक रूप से उत् मत्स्य बीज उपलब्ध कराना शामिल है। मिशन के दौरान 3 और 4 जून को राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ विस्तृत समीक्षा बैठकें आयोजित गईं जिनमें योजना के संचालन एवं क्रीयनवन से संबन्धित बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। परियोजना की अब तक प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिशन के सदस्यों ने कहा कि यूपीएग्रीज उत्तर प्रदेश में जलवायु प्रभावित जनपदों में आधुनिक, विज्ञान–आधारित, और बाजारोन्मुख कृषि विकास को गति देने के साथ–साथ किसानों आय और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 5 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित अद्यतन प्रस्तुति एवं भविष्य की कार्ययोजना बैठक परियोजना के विस्तार, नवाचारों और साझेदारियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव (कृषि), अपर परियोज समन्वयक (यूपीडास्प) तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महिला से अभद्रता और अश्लील हरकत के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। माल थाना क्षेत्र में एक महिला एवं उसके परिजनों के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत, गाली–गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार थाना माल पर प्राप्त तहरीर में शिकायत की गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक महिला तथा उसके परिजनों के साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए अश्लील हरकतें की गईं और गाली–गलौज की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना माल में मुकदमा अपराध संख्या 0122ध्2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 एवं 352 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना माल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी सर्वेश तथा गुड्डू पुत्रगण गुरू प्रसाद निवासी ग्राम खजहापुरवा मजरा टिकरीकला, थाना माल, जनपद लखनऊ को हिरासत में ले लिया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मामले से संबंधित अन्य साक्ष्यों का भी संकलन किया जा रहा है, ताकि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पेप्सिको इंडिया ने लॉन्च किया प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक 'एड्रेनलिन रश'

लखनऊ, (संवाददाता)। पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय एनर्जी ड्रिंक ब्रांड 'एड्रेनलिन रश' को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने 'ए–रश, ए–गेम ऑन' अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत एक नई प्रचार फिल्म जारी की गई है। कंपनी का कहना है कि यह लॉन्च उसके एनर्जी ड्रिंक्स पोर्टफोलियो के विस्तार और युवा उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।पेप्सिको इंडिया की एनर्जी ड्रिंक्स श्रेणी प्रमुख दीक्षा बजाज ने कहा कि एड्रेनलिन रश को नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ब्रांड जुनून, प्रदर्शन और लक्ष्य हासिल करने की भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार यह अभियान उस पीढ़ी की सोच को सामने लाता है जो लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है।पेप्सिको इंडिया के इंडिया बिजनेस यूनिट बेवरेजेज के मुख्य विपणन अधिकारी तरुण भगत ने कहा कि भारत में एनर्जी ड्रिंक्स बाजार लगातार बढ़ रहा है और उपभोक्ता अपनी विभिन्न जरूरतों के अनुरूप उत्पादों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एड्रेनलिन रश के माध्यम से कंपनी प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक खंड में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रही है।कंपनी के अनुसार एड्रेनलिन रश 60 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। इसे दो वैरिएंटकृ'पैशन रश' और 'क्लासिक रश'कृमें पेश किया गया है। प्रीमियम कैन पैक में उपलब्ध इस उत्पाद में कैफीन, टॉरिन और विभिन्न विटामिन शामिल हैं।

जल, जंगल जमीन हमारी संस्कृति की आधारशिला : डा विवेक पांडेय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, के पर्यावरण विज्ञान विभाग के समर ट्रेनिंग छात्रों ने रूरल कलीचाबाग स्थित जल कल विभाग में मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण दिवस 2026 ष्इंस्पायर बाय नेचररू फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचरष पर कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। सहायक आचार्य डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय ने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति व सभ्यता की आधारशिला हैं। उन्होंने बढ़ते तापमान, घटते भूजल स्रोत, वायु प्रदूषण व जैव विविधता क्षरण पर चिंता जताते हुए जल संरक्षण, जल संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा प्राकृतिक जल स्रोतों व आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। डॉ. पाण्डेय ने नदियों की स्वच्छता को पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और भारतीय संस्कृति में नदियों व वनों को मां व देवता रूप में पूजने का महत्व रेखांकित किया। कार्यक्रम में क्वालिटी मैनेजर केमिस्ट श्रुति मिश्रा, निलेश जायसवाल, अंकित यादव, पुष्कर सिंह व स्नातककृपरास्नातक छात्र निधि, श्रद्धा, अनमोल, सिद्धार्थ, सुमित, हरिओम तथा शोधार्थी चंद्र भूषण उपस्थित रहे। आयोजकों ने समुदाय आधारित संरक्षण और जागरूकता अभियान तेज करने का संकल्प लिया।

पीयू संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, समर्थ पोर्टल पर करे आवेदन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जून से समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के निर्देश पर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं छात्र हितैषी बनाने के उद्देश्य से सभी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करनी होगी। इसके बाद वे अपनी पसंद के महाविद्यालय एवं विषय का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार समर्थ पोर्टल का लिंक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।इस मामले में शुक्रवार को जानकारी लेने पर कुल सचिव केश लाल ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएगी। ऐसे में प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्राओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनेगी तथा अभ्यर्थियों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।

पीडीए आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सपा का प्रदर्शन, भाजपा सरकार मंहगाई की जननी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शुक्रवार को जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने जनसमस्याओं को लेकर जोरदार धरना–प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और आठ सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। धरने में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पीडीए आरक्षण घोटाला, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अघोषित बिजली कटौती तथा पेट्रोल–डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। वक्ताओं ने जल जीवन मिशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजनाओं में कथित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पीडीए समाज के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव 'ललई' ने फर्जी एनकाउंटर के मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को घेरते हुए कहा कि संविधान के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था चलनी चाहिए। धरने को विधायक तूफानी सरोज, लकी यादव, डॉ. रागिनी सोनकर, पंकज पटेल समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपकर जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। धरना–प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है : कुलपति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना भवन परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. वन्दना सिंह ने अशोक का पौधा लगाकर किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर कुलपति प्रो. वन्दना सिंह ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जन–जागरूकता ही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शशिकांत यादव ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद सिंह, प्रो. अजय द्विवेदी, प्रो. अविनाश पाथर्डीकर, डॉ. श्याम कन्हैया, डॉ. मनोज पांडेय, राधेश्याम सिंह, उत्कर्ष सिंह, शीलनिधि सिंह, सर्वेश यादव सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएचसी चिनहट में हर्बल पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), चिनहट, लखनऊ में त।ट थ्वनदकंजपवद द्वारा "Inspired by Nature- For Climate- For Our Future-" Fkhe के अंतर्गत हर्बल पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में त।ट थ्वनदकंजपवद की अध्यक्ष रचना सिसोदिया ने पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है। इस अवसर पर डॉ. वाई. पी. सिंह (एमेरिटस साइंटिस्ट) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तथा औषधीय पौधों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में डॉ. चंदन कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, सीएचसी चिनहट, डॉ. शोभना यादव (बाल रोग विशेषज्ञ), अंकुर दिवाकर नितीश सिंह (एचईओ), कंचन सिंह (बीपीएम), डीईओ, स्टाफ नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर एलोवेरा, पीपल, अश्वगंधा, पुदीना, अर्जुन, नीम, अशोक, तुलसी, मीठी नीम तथा आंवला सहित विभिन्न औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व के पौधों का रोपण किया गया। प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कार्यक्रम का उध्द्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में हरित वातावरण को बढ़ावा देना, औषधीय पौधों के महत्व के प्रति जागरुकता फैलाना तथा जलवायु संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना था।

डाबर पुदीन हरा ने किया वंडर हर्ब : पुदीने के महत्व को प्रतिष्ठित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभों का प्रचार करने के अपने मिशन में आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे बड़ी विज्ञान आधारित आयुर्वेद कंपनी, डाबर इंडिया लिमिटेड ने पुदीना को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरूआत की गयी। इस मौके पर डा. आशीष जायसवाल, डाबर इण्डिया लिमिटेड, कार्पोरेट कम्युनिकेशन के सीनियर मैनेजर दिनेश कुमार मौजूद थे। इस मौके पर पुदीना की उपयोगिता को लेकर डा. आशीष जायसवाल ने बताया कि पुदीना एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स युक्त होता है जो मानव पेट के लिए खासकर तेज गर्मी के दौरान चमत्कार कर सकते हैं, गर्म–लहरों और बढ़ते पारा के स्तर की त्वरित आवृत्ति के साथ, गर्मियों के मौसम के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। इस तीव्र मौसम में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए, डाबर उन लोगों को पुदीना के उपयोग की सलाह देते हैं जो दिन में लंबे समय तक धूप में रहते हैं और आम गर्मी की बीमारियों के शिकार होते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड, डायरेक्टर–मार्केटिंग, श्री श्रीराम पद्मनाभन ने कहा: "जीवन शैली में विकसित रुझानों और उपभोक्ताओं के काम का पैटर्न देखने पर पता चलता है कि आज सभी बहु–मुखी कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रभावी और प्राकृतिक समाधान की आवश्यकता होती है। डाबर, सबसे भरोसेमंद हेल्थकेयर कंपनी के रूप में, दैनिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पारंपरिक आयुर्वेद को उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को मजबूत करता है और पुदीन हरा कई गैस्ट्रिक विकारों के लिए एक निश्चित समाधान है। गर्मियों के मौसम के दौरान प्रचलित कई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, पुदीन हरा बदहजमी, गैस और एसिडिटी जैसे पेट की समस्याओं के समाधान में मदद करता है "। डा. आशीष जायसवाल, आयुर्वेद फिजिशियन ने आगे कहा, "आयुर्वेद की पांडुलिपियों में आधुनिक समय की बीमारियों का सबसे अच्छा प्रबंधन गहराई से छिपा हुआ है। पुदीना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 3,000 साल पुरानी है और इसे वंडर हर्ब के रूप में नामित किया गया है जो मानव पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। पुदीना में मौजूद मेन्थॉल पाचन के लिए जरूरी एंजाइमों को उत्तेजित करता है, पेट की मांसपेशियों को आराम देता है, अपचन और मरोड़ की संभावनाओं को कम करता है। यह पेट की ऐंठन, अम्लता और पेट फूलना आदि पर इसके शांत प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। आज बाजार में बहुत से एंटासिड उपलब्ध हैं जिनमें एल्यूमीनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कठोर रसायनों होते हैं जो नियमित रूप से लेने पर स्वास्थ्य पर कुछ हानिकारक प्रभाव छोड़ सकते हैं। डाबर पुदीन हरा जो डाबर का 100 साल पुराना ब्रांड है, गैस, अपचन, पेट दर्द और अम्लता जैसी सभी पेट समस्याओं में तेजी से और प्रभावी राहत देने के लिए पुदीना सत्व के गुणों के साथ एक आयुर्वेदिक उपचार है। पुदीन हरा कई रूपों जैसे टैबलेट ध् तरल पदार्थ, पाउडर, पुदीन हरा फिज के रूप में उपलब्ध है – जो कठोर रसायनों के विपरीत अम्लता का एक प्राकृतिक उपचार है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर ओमैक्स मेट्रो सिटी में हुआ वृहद पौधारोपण, आमजन की सहभागिता के साथ 10 हजार पौधरोपण का संकल्प

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ओमैक्स मेट्रो सिटी में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया. इस मौके पर 10 हजार पेड़–पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया जो चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे । पहले चरण में विविध प्रजातियों के पांच हजार पौधे रोपित किए गए. 690 एकड़ में फैली यह ओमेक्स मेट्रो सिटी टाउनशिप शहर के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल है। इस अभियान के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने और लोगों को हरियाली के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर ओमैक्स ने आमजन से भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर साइट में आकर पौधारोपण की अपील की। बड़ी संख्या में लोगों ने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कंपनी की ओर से कहा गया है कि जो भी लोग इस अभियान में शामिल होकर पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ओमैक्स की टीम करेगी। कंपनी का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी से यह अभियान और प्रभावी बनेगा। ओमैक्स के एमडी श्री मोहित गोयल . ने कहा कि प्रकृति हमें जीवन देती है। ऐसे में अब समय आ गया है कि हम प्रकृति को जीवन दें। पृथ्वी को बचाना विकल्प नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम सभी संकल्प करें कि हम हर छोटे कदम से पर्यावरण को हरा–भरा और स्वच्छ बनाएंगे। ओमैक्स के बिजनेस हेड अंजनी कुमार पण्डेय ने कहा कि पौधे लगाना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए जरूरी जिम्मेदारी भी है। इसी सोच के साथ यह अभियान आयोजित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और शहर को हराभरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ओमैक्स मेट्रो सिटी में द नेस्ट, कासिया और हाईस्ट्रीट जैसे प्रोजेक्ट लोगों के बीच काफी पसंद किए जा रहे हैं। आउटर रिंग रोड के पास स्थित द नेस्ट बेहतर लोकेशन और सुविधाओं की वजह से खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आने वाले समय में यहां कई और नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाने की योजना है।

विवेक सृष्टि परिसर में कोविदार वृक्ष का हुआ पौधरोपण

अयोध्या।विश्व पर्यावरण दिवस व रामराज्य संकल्प अभियान के तहत अयोध्या के विवेक सृष्टि परिसर में कोविदार का पौधरोपण किया गया।इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्माकुमारी समाज के सहयोग से किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक,धार्मिक और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए।पौधरोपण कार्यक्रम में विवेक सृष्टि के संस्थापक डॉ. चौतन्य,महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, इंजीनियर रवि तिवारी,ब्रह्माकुमारी समाज के धर्मगुरु राजयोगी हरिलाल भानुशाली और बीके मुकेश ने संयुक्त रूप से पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।इस मौके पर उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोविदार वृक्ष का संबंध भगवान श्रीराम के वंश से माना जाता है।इस कार्यक्रम का विशेष महत्व इसलिए भी रहा।

विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर आज आम आदमी पार्टी, जिला अयोध्या के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भीषण बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरों तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनिल प्रजापति के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला प्रभारी अयोध्या संजीव निगम ने कहा कि बाराबंकी में बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था का दुखद उदाहरण है।उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, तब सरकार के जिम्मेदार मंत्री समस्याओं का समाधान करने के बजाय गैर–जिम्मेदाराना बयानबाजी में व्यस्त हैं। जनता को राहत देने के बजाय उसकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है।जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था सुधारने के बड़े–बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। गांवों और शहरों में घंटों बिजली गुल रहने से जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। उद्योग, व्यापार, खेती और विद्यार्थियों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अघोषित बिजली कटौती बंद करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बिजली दरों में वृद्धि पर रोक लगाने, स्मार्ट मीटर एवं फर्जी बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराने तथा प्रदेशवासियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की मांग की।इस कार्यक्रम में गायत्री मिश्रा,शारजाह मास्टर,रघुनाथ प्रसाद,नीलेश चतुर्वेदी,रामजी लाल वर्मा,यू के दिवेदी,कृष्णानाथ यादव,अखिलेश कुमार ,कुलभूषण साहू, मोहित महाराज राजीव पाठक,आदर्श कुमार, गुड़िया राईन,आदर्श कुमार,दिवस सिंह, मनोज दुबे, साक्षी , नेहा, प्रभावती, राहुल, रोली मौजूद रहे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।सरकारी अस्पतालों में केवल ड्रीफकेस मोबाइल ऐप के ही माध्यम से ओपीडी दवा पर्चा बनाने का व हस्तलिखित मैन्युअल पर्चा ना बनाने की समस्या को लेकर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राहुल पांडेय व प्रदेश सचिव दीपक पांडेय ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर अयोध्या व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में सौंपा।ज्ञापन में मांग किया गया है कि समाज में तमाम अनपढ़ व गरीब व्यक्तियों को जिनके पास या तो एंड्राइड मोबाइल नहीं है, अथवा एंड्राइड मोबाइल ज्ञान न होने पर संचालित नहीं कर पाते है।जिससे सरकारी अस्पताल का दवा पर्चा ना बनने के कारण मेडिकल सुविधा से वंचित रह जाता है। ऐसी दशा में क्तपमबिंम ऐप के अतिरिक्त मैन्युअल हस्तलिखित अस्पताल ओपीडी पर्चा बनाने की व्यवस्था पूर्व की भांति जनहित में किया जाना अति आवश्यक है, जिससे अनपढ़ व गरीब व्यक्ति भी चिकित्सा सुविधा ले सके।उन्होंने ज्ञापन की प्रतिलिपि स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन व जिलाधिकारी को भी प्रेषित की है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ पौधरोपण

अयोध्या।शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकासखंड मया बाजार की ग्राम पंचायत सरैया में मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अंतर्गत चिन्हित तालाब पर, ग्राम पंचायत अंकारीपुर के गौशाला में एवं विकासखंड पूरा बाजार के ग्राम पंचायत अलावलपुर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर जिला समन्वयक दीपक सेन, अविरल पाठक, संबंधित खंड प्रेरक, कंसलटिंग इंजीनियर, सचिव, ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।।

तेज धूप के बाद अचानक छाए बादल, मौसम विशेषज्ञ बोले, जारी उतार–चढ़ाव रहेगा

गोरखपुर, (संवाददाता)। जून की शुरुआत में मौसम का मिला–जुला असर देखने को मिला। मंगलवार को अचानक मौसम ने फिर करवट ली। तेज धूप के बाद बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश के बावजूद शहर का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा। सुबह के समय बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकलने से गर्मी फिर बढ़ गई। जिले में 3.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अधिकतम आर्द्रता 72 प्रतिशत और न्यूनतम 38 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह उतार–चढ़ाव बना रह सकता है। बीच–बीच में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। किसानों के लिए यह वर्षा फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बढ़ी है और खरीफ फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

चौक स्थित सब्जी मंडी में दुकानों के लिए काम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर अवैध मकान पर चला बुलडोजर

अयोध्या।कोतवाली नगर क्षेत्र के चौक क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी सराय मस्जिद के पास प्रस्तावित लगभग 200 दुकानों वाला आधुनिक परिसर काम्प्लेक्स बनाने की योजना है। बताते चले यह भूमि नजूल की है।इसको लेकर शुक्रवार को चौक क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी सराय मस्जिद के पास जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस मौके पर नजूल की जमीन पर बने अवैध घरों तथा दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान किसी प्रकार की वहां पर अशांति की व्यवस्था न उत्पन्न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती रही। इस मौके पर प्रभावित परिवारों को मुआवजे के चेक भी वितरित किए गए वहीं कई लोगों ने मुआवजे की रस को काम बताते हुए इसका विरोध किया जिसके चलते थोड़ी देर के लिए स्थित तनावपूर्ण हो गई।पीड़ितों ने मांग की कि उन्हें इतना मुआवजा मिले जिससे वे नई जमीन खरीदकर घर बना सकें।पीड़िता नजमा ने बताया कि उन्हें केवल 40 हजार रुपये का मुआवजा मिला है। नजमा ने पति की बीमारी और बच्चों के पालन–पोषण की चिंता जताई।

डीईओ ने आबकारी भवन परिसर मे किया पौधरोपण

अयोध्या।शुक्रवार को आबकारी भवन परिसर मे डीईओ डाक्टर निरंकार नाथ पाण्डेय ने पौधरोपण किया।इस मौके पर उन्होंने पीपल,नीम,पाकड़, जामुन, लीची, बेल सहित दो दर्जन से अधिक किस्म के पौधे लगाए।इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधरोपण करना ही जरुरी नही है जबकि उन पौधों का बीच–बीच में देखभाल भी करना जरूरी रहता हैउनके अलावा आबकारी इंस्पेक्टर अरविंद शुक्ला,विवेक पाठक सहित विभाग के अन्य कर्मियों ने भी पौधारोपण किया।

कलेक्ट्रेट परिसर में पांच गुमटियों के ताले टूटे

गोरखपुर, (संवाददाता)। कलेक्ट्रेट परिसर में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार देर रात चोरों ने पांच गुमटियों को निशाना बनाकर लैपटॉप, नकदी, पंखे और स्टॉम्प पेपर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 10.30 बजे स्टॉम्प वेंडर पहुंचे तो गुमटियों के ताले टूटे हुए थे। कुछ देर में ही पता चला कि पांच गुमटियों के ताले और दरवाजे तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस के निरीक्षण के बाद अरविंद कुमार ने कैंट थाने में तहरीर दी कि उनकी गुमटी का ताला तोड़कर लैपटॉप एवं 2200 रुपये चोरी हो गए हैं। दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष शिवाकांत पांडेय ने बताया कि उनके यहां से पंखा खोल लिया गया है।

पुलिसकर्मी के खाते से 1.39 लाख की साइबर ठगी, फोन हैक कर उड़ाए रुपये

गोरखपुर, (संवाददाता)। साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी के बैंक खाते से 1.39 लाख रुपये यूपीआई के जरिये निकाल लिए गए। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात जालसाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार, गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के जोहरपुर गांव निवासी गोपाल जय सिंह, वर्तमान में यातायात पुलिस गोरखपुर में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि सात मई 2026 को उनके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से बिना जानकारी के तीन बार में रुपये निकाल लिए गए। रिकॉर्ड के अनुसार, पहली ट्रांजेक्शन 70 हजार रुपये की हुई, दूसरी बार 20 हजार और तीसरी ट्रांजेक्शन 49,986 रुपये की गई। इस तरह कुल 1.39 लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया फोन हैक कर की गई क्योंकि उनके मोबाइल पर किसी भी ट्रांजेक्शन का अलर्ट मैसेज नहीं आया। मामले का पता तब चला जब उन्होंने बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक से भी संबंधित खातों और ट्रांजेक्शन डिटेल्स की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि रुपये के लेन–देन की कड़ी को ट्रेस किया जा सके। साइबर एक्सपर्ट उपेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर मोबाइल हैकिंग, फिशिंग लिंक या ओटीपी चोरी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और ट्रांजेक्शन के स्रोत की गहन जांच कर रही है।

एडी चिकित्सा स्वास्थ्य व सीएमओ अयोध्या कार्यालय पर हुआ वृक्षारोपण

अयोध्या। शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एडी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल,अयोध्या व सीएमओ अयोध्या कार्यालय के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस मौके पर एडी डॉ ब्रजेश कुमार सिंह चौहान, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ रमेश कुमार, सीएमओ डॉ देवेंद्र कुमार ,जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ पी सी भारती सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।वृक्ष न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण को कम करने तथा जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया।

विभिन्न मांगो को लेकर डिप्टी सीसीएम पीएएसको सभासद आरती जायसवाल ने दिल्ली मे सौपा मांग पत्र

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अयोध्या धाम जनपद के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकटो की बिक्री के साथ सुबह 8 बजे से शाम 20 बजे तक(12 घंटे) आरक्षण टिकटों की बिक्री बहाल किये जाने की मांग को लेकर गोसाईगंज नगर पंचायत की सभासद एवं जय बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति (रजि0) की अध्यक्ष आरती जयसवाल नई दिल्ली बड़ौदा हाउस पहुंच गई।इस दौरान उन्होंने मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) के नाम सम्बोधित मांग पत्र को उनकी न मौजूदगी मे उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ध्यात्री सेवा(डिप्टी सीसीएम–पीधएस)कुलदीप तिवारी को सौपी एवं जनहित में लखनऊ–बाराबंकी–जौनपुर वाराणसी रेलखंड स्थित पूर्व सांसद एवं मौजूदा एमएलसी हरिओम पांडे के होम स्टेशन गोशाईगंज मे आरक्षण टिकटों की बिक्री 12 घंटे किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से वकालत की।उन्होंने कहा कि दर्जनों बार पत्र भेजने के बाद भी आज तक यात्रियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।जब कि इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय विधायक एवं कई सांसदों ने पत्र भी दिया,परन्तु नतीजा शून्य रहा।उन्होंने बताया कि गोशाईगंज स्टेशन पर आरपीएफ के साथ जीआरपी चौकी पर सुरक्षाकर्मी तैनात होने के साथ ही पर्याप्त संख्या में बुकिंग क्लर्क भी तैनात हैं।बावजूद यात्री सुबिधा बढ़ाने मे हीलाहवाली की जा रही हैं!मामले में उप मुख्य यात्री प्रबंधक यात्री सेवा(डिप्टी सीसीसीएम (पीधएस) श्री तिवारी ने सभासद को आश्वस्त किया कि गोशाईगंज रेलवे स्टेशन पर उनके द्वारा की जा रही यह मांग बहुत पुरानी है तथा उक्त सुबिधा की बहाली के लिए इसी सप्ताह सी0 डीसीएम लखनऊ को पत्र भेजा जायेगा।

बुंदेलखंड अधिवक्ता महासंघ ने रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी, (संवाददाता)। बुंदेलखंड अधिवक्ता महासंघ ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ता विरोधी चौम्बर एलाटमेंट रूल्स 2026 को संशोधित कर बिना रेंट के चौम्बर एलाटमेंट करने की मांग किया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव की अनुपस्थिति में बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजकुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि टेंटटिव लिस्ट में आपत्ति दाखिल कर ने की तिथि 5 जुलाई तक बढ़ाई जाय और चौम्बर एलाटमेंट के मुद्दे पर बार एसोसिएशन की आमसभा जुलाई के पहले सप्ताह में बुलाई जाय। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे से मार्बल हाल के पास अधिवक्ता एकत्र होने लगे थे, इस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में पहुंच कर उन्हें पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लागू किया गया चौम्बर एलाटमेंट रूल्स 2026 पूरी तरह अधिवक्ता विरोधी है और विना अधिवक्ता ओं से आपत्तियां आमंत्रित किए लागू किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, अधिवक्ता ओं द्वारा उठाईं जा रही आपत्तियों पर विचार कर रूल्स में संशोधन किया जाय। ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता आफीसर आफ कोर्ट माना जाता है इस लिए सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए बिना रेंट के चौम्बर एलाटमेंट किए जाय , धरोहर राशि 20 साल से अधिक प्रैक्टिस कर ने वाले अधिवक्ता ओं से 25000 रूपये और 20 साल से कम प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता ओं से 10000 रूपए लिए जाय। ज्ञापन देने वालों में बुंदेलखंड अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महासचिव जगदीश सिंह बुंदेला, उपाध्यक्ष सुशील कुमार यादव, पी के राव, सचिव चंद्रकांत द्विवेदी, सार्थक सिंह, कोषाध्यक्ष सोम नारायण मिश्र, बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता सी पी उपाध्याय, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हरवंश सिंह, आर पी तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, आशुतोष त्रिपाठी, आशुतोष पाण्डेय, ए के तिवारी, सुभाष चन्द्र सिंह, राय साहब यादव, धर्मेंद्र सिंह सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।

पल्सर बाइक में भीषण आग लगने से जलकर राख

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के मवई चौराहा स्थित अतुल चाट कॉर्नर के सामने गुरुवार को मवई चौराहा निवासी बाबूलाल सोनी की पल्सर बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई।देखते ही देखते बाइक ध्–धू कर जलने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह राख हो गई।घटना से मौके पर अफरा–तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना पर पहुंचे मवई थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया।पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।